

# शुगर इंडस्ट्री की इम्पोर्ट इयूटी बढ़ाकर 60% करने की डिमांड

[जयश्री भोसले | पुणे]

नए सीजन की चीनी की आवक बढ़ने, अधिक प्रॉडक्शन की संभावना और कुछ मिलों की ओर से जल्दबाजी में बिक्री करने से पिछले एक पखवाड़े में मिलों के लिए चीनी के दाम लगभग 5 पैसे कम हुए हैं। इस वजह से शुगर इंडस्ट्री ने इम्पोर्ट इयूटी में बढ़ोतरी करने और ट्रेडर्स पर स्टॉक लिमिट को हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (UPSMA) के सेक्रेटरी, दीपक गुप्तारा ने बताया, 'चीनी की कीमतें गिर रही हैं। हमें पिछले तीन सप्ताह में 200 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। हमने चीनी पर इम्पोर्ट इयूटी बढ़ाकर 60 पैसे करने की मांग की है।' अभी चीनी पर इम्पोर्ट इयूटी 50 पैसे की है।

उत्तर प्रदेश में चीनी के मिलों के लिए दाम पिछले तीन सप्ताह में 36.50 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 34 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए हैं। राज्यों की मिलों के पास पिछले वर्ष के प्रॉडक्शन की करीब 14 पैसे चीनी है। नए सीजन की चीनी मार्केट में आने के कारण पुरानी चीनी डिस्काउंट पर बेची जा रही है। उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलों में से 109 ने पेरार्इ शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में नई चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। सर्दियों में कोल्ड ड्रिक्स और आइसक्रीम की खपत कम होने और कोई बड़ा त्योहार न आने के कारण चीनी की मांग कम रहती है।

महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में चीनी मिलें जल्दबाजी में बिक्री कर रही हैं। राज्य की एक प्राइवेट शुगर मिल, नेचुरल शुगर एंड अलायड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, बी बी थॉम्पे ने बताया, 'मिलों को आने वाले दिनों में दाम और घटने की आशंका है और इसी वजह से वे जल्दबाजी में बिक्री कर रही हैं।' मुंबई में S30 ग्रेड चीनी का होलसेल दाम गुरुवार को 3,440-3,552 रुपये प्रति क्विंटल था। 15 नवंबर को यह 3,610-3,662 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था। इसमें एक पखवाड़े में 4.7 पैसे की कमी आई है। चीनी मिलों के पुराना स्टॉक निकालने के कारण कीमतें गिर रही हैं। महाराष्ट्र के एक मिल मालिक ने कहा, 'पिछले शुगर सीजन में प्रॉडक्शन बहुत अधिक गिरने के बावजूद महाराष्ट्र में मिलों के पास पुरानी चीनी मौजूद है, जिसे वे कीमतें बढ़ने की उम्मीद में रोक रही हैं।'

कुछ मिल मालिकों ने ट्रेडर्स से एडवांस पेमेंट ले ली थी और इस वजह से उन्हें चीनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि, शुगर इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार कीमतों को बहुत अधिक नहीं गिरने देगी क्योंकि 2017-18 के लिए गन्ने का दाम बढ़ाया गया है।

एक सूत्र ने बताया कि जल्द ही ट्रेडर्स पर स्टॉक लिमिट हटाने के फैसले की घोषणा की जा सकती है।

*The Economic Times*

1-12-17.

